

प्रेषक,

श्री एस0एम0ए0 आब्टी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महा निबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-2 अधीनस्थ न्यायालय।

दिनांक: दिनांक 20 मई, 2009

विषय:- रिट पिटीशन सी।संख्या-1022/1989: आल इण्डिया जेज
एसोसियेशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में
मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-1-08
संपठित आदेश दिनांक 15-3-2008 के संदर्भ में अधीनस्थ
न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के
सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। इंडी टी आयोग।
द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

महा निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, के अर्धावसकीय पत्रांक
12957/वी.ई.-60/एडमि।डी दिनांक 14-10-2008 के संदर्भ में तथा
शासनादेश संख्या-2071/सात-न्याय-2-08-132जी/08, दिनांक 29 सितम्बर,
2008 तथा शासनादेश संख्या-3565 व 3566/सात-न्याय-2-08-132जी/08
दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 एवं संख्या-3568/सात-न्याय-2-08-227 जी/08,
दिनांक 18 अक्टूबर, 2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि
रिट पिटीशन सी।संख्या-1022/1989: आल इण्डिया जेज एसोसियेशन तथा
अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित
आदेश दिनांक 22-1-2008 संपठित आदेश दिनांक 15-7-2008 के अनुपालन में
अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के
सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। इंडी टी आयोग। द्वारा की गयी
विभिन्न संस्तुतियों के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त अधीनस्थ न्यायालयों के
लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश के वैयक्तिक सहायक, जिला संशोधित
पदनाम शासनादेश संख्या-3568/सात-न्याय-2-08-227 जी/08, दिनांक
18-10-2008 द्वारा "स्टेनोग्राफर ग्रेड-1" कर दिया गया है, का वेतनमान
₹06500-10500/- को उच्चैकृत करते हुये वेतनमान ₹07450-11500/-

किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय विम्बलिखित प्रतिबन्धों के अधीन तब स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क- स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 के लिये उच्चिकृत वेतनमान दिनांक 1-4-20 प्रभावी माना जायेगा ।

ख- उच्चिकृत वेतनमान में स्टेनोग्राफर-1 का प्रारम्भिक वेतन वित्त नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के मूल नियम 22 के नीचे दिये गये सम्परीक्षित विदेशों के पुस्तक-4 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा । उन्हें उच्चिकृत वेतनमान वित्तीय नियम संग्रह -खण्ड-2 भाग-2, 4 के मूल नियम -23।1 के अनुसार विकल्प देना की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी ।

2- उपयुक्त पदों पर होने वाला व्यय बालू वित्तीय वर्ष 2009-20 आय-व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अंतर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासनिक जेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश" की सुसंगत इकाइयों के कामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त वेतन आयोग अंश-1 के असासकीय संख्या 0आ0-1-250/अस-09, दिनांक 6-5-2009 में प्राप्त उनकी सडमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

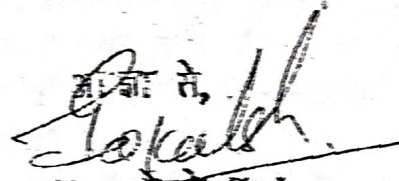
संस० सम० सं० आबदी
प्रमुख सचिव ।

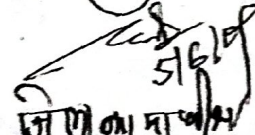
संख्या-1374।।/सात-न्याय-2-09, तददिनांक

प्रतिलिपि विम्बलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त जजपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश ।
- 2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 3- वित्त वेतन आयोग अंश-1/2 तीन तीन प्रतियों में ।
- 4- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी।।/2 तथा आडिट।/2 उ०प्र०, इलाहाबाद ।

- 5- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन, न्याय विधि कोष्ठक, बी०सी०आई० भवन, 21 राजस्व स्वेन्घु, ऊर्ध्वर मार्ग, नई दिल्ली।
- 6- श्री श्रीधर कुमार मिश्रा, एडवोकेट जनरल रिकार्ड, मं० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 7- वित्त [आय-व्ययक] अनुभाग-1/2, वित्त [व्यय-नियंत्रण] 1-12
- 8- न्याय अनुभाग-9 [बजट]
- 9- गार्ड बुक हेतु
- 10- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

सचिव, 
[570 गोरखपुर]
विशेष सचिव।

अवलोकित, सुमनस्य हेतु
प्रति [कोष] व [अनुभाग] के
की ओर।

जि.पी.आ. प्र.प.म.
5-6-69